भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1771

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक) को दिया गया

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना

1771. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नकदी के विकल्पों को व्यापक और गहन बनाने हेतु डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लिंचपिन ट्रांजैक्शन प्रणाली के रूप में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) व्यवस्था इस क्षेत्र में बदलाव लाने में एक बड़ा कारक रही है और यदि हां, तो विगत एक वर्ष में यूपीआई के माध्यम से हुए लेनदेन की कुल मासिक मात्रा कितनी है;

(ग) क्या बैंकिंग क्षेत्र अपने मुख्य कारोबार के विकास के लिए भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाने को पूरी तरह तैयार है; और

(घ) यदि हो, तो क्या सरकार इस संबंध में बैंकों को कोई प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (घ): डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना में बैंकों को भीम-यूपीआई प्लेटफॉर्म पर रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य (यानी 2,000 रुपये तक) के लेनदेन का उपयोग करके प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। यह योजना यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे को किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल भुगतान समाधान के रूप में भी बढ़ावा देती है। एमईआईटीवाई ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इस योजना के लिए 2,600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

प्रोत्साहन योजना ने बैंकों को एक सुदृढ़ डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर और आबादी के सभी क्षेत्रों और वर्गों में कम लागत वाले डिजिटल भुगतान माध्यम के रूप में रूपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करके डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया है।

बैंक अपने ग्राहकों को डिजिटल मोड में उन्नत और निर्विघ्न बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नवीनतम डिजिटल तकनीकों को अपना रहे हैं। इसके अलावा, देश के लोगों को निर्विघ्न और निर्बाध बैंकिंग लेनदेन की सुविधा के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।

डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और देश में डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत सरकार, आरबीआई, एनपीसीआई और बैंकों द्वारा कई पहल की गई हैं। कुछेक पहल भीम-यूपीआई, यूपीआई-123, आधार पेमेंट ब्रिज, एईपीएस आदि हैं।

इन पहलों के परिणामस्वरूप, भारत में डिजिटल लेन-देन में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है, जो पिछले चार वित्तीय वर्षों में डिजिटल लेन-देन की संख्या में वृद्धि के रूप में परिलक्षित होता है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

वित्तीय वर्ष	**संख्या (करोड़ में)**
2018-19	2326.02
2019-20	3400.25
2020-21	4374.45
2021-22	7197.68

स्रोत: आरबीआई

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है, वर्ष 2018-19 से गत चार वर्षों के दौरान डिजिटल भुगतान की संख्या में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 21-22 में दर्ज यूपीआई लेनदेन 45 बिलियन था, जो पिछले 3 वर्षों में 8 गुना वृद्धि और पिछले 4 वर्षों में 50 गुना वृद्धि को दर्शाता है। पिछले वर्ष यानी 2022 के दौरान दर्ज यूपीआई लेनदेन के माह-वार आंकड़े निम्नानुसार हैं:

माह	**यूपीआई लेनदेन की संख्या (करोड़ में)**
जनवरी -22	461.715
फरवरी -22	452.749
मार्च -22	540.565
अप्रैल -22	558.305
मई-22	595.52
जून-22	586.275
जुलाई-22	628.84
अगस्त -22	657.963
सितंबर -22	678.08
अक्टूबर-22	730.542
नवंबर -22	730.945
दिसंबर -22	782.949

स्रोत-एनपीसीआई

*****